महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष-6 | अंक-20 | मुंबई, 16 से 30 नवम्बर 2018 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

गेहूं बुआई में तेजी, दलहन और तिलहन की बुआई कम

नई दिल्ली (कासं)। गेहूं की बुआई में तेजी आनी शुरू हो गई है क्योंकि मौजूदा रबी सत्र में अब तक इस फसल के तहत रकबा 20 फीसदी तक बढ़कर 15.19 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है, लेकिन दलहन और तिलहन का रकबा एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में कमजोर बना हुआ है।

अक्टूबर से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाती है और मार्च से इसकी कटाई होने लगती है। गेहूं रबी सीजन की मुख्य फसल है। एक साल पहले 12.65 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार गेहूं बुआई में अधिकतम वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है जहां किसानों ने इस सीजन में अब तक 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इस फसल की बुआई की है, जो एक साल पहले के 2.17 लाख हेक्टेयर से काफी अधिक है. पंजाब में गेहूं का रकबा इस साल अब तक 4.68 लाख हेक्टेयर पर और उत्तर प्रदेश में 1.73 लाख हेक्टेयर पर है। हालांकि दलहन की बुआई में तेजी नहीं आई है क्योंकि दलहन का रकबा 39.05 लाख हेक्टेयर पर है जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 54.34 लाख हेक्टेयर पर था। दलहन का रकबा सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में कमजोर बना हुआ है। कर्नाटक में दलहन का रकबा पिछले साल के 11.28 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 5.52 लाख हेक्टेयर है जबकि मध्य प्रदेश में यह रकबा 17.62 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12.26 लाख है। उत्तर प्रदेश में दलहन का रकबा इस सीजन में अब तक 5.31 लाख हेक्टेयर पर है जो एक साल पहले की समान अवधि में 7.47 लाख हेक्टेयर पर था, जबकि राजस्थान में यह 5.29 लाख हेक्टेयर पर है जो पिछले साल 6.65 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह तिलहन का रकबा 37.09 लाख हेक्टेयर पर है जो पिछले साल 40.86 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज के लिए यह आंकड़ा पिछले साल के 22.65 लाख हेक्टेयर की तुलना में 14.14 लाख हेक्टेयर है। धान का रकबा इस सीजन में अब तक 5.24 लाख हेक्टेयर पर है जो एक साल पहले की समान अवधि में 7.66 लाख हेक्टेयर था. कुल मिलाकर, सभी रबी फसलों का रकबा अब तक 110.71 लाख हेक्टेयर के साथ कमजोर है जो पिछले सीजन के समान समय में 138.16 लाख हेक्टेयर था।

57 साल बाद मुंबई में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

मुंबई (कासं)। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 नवंबर से मुंबई में शुरू होने जा रहा है। दो हफ्तों तक चलने वाले इस सत्र की घोषणा गुरुवार को की गई थी। विपक्ष ने सत्र की छोटी अवधि के लिए सरकार की निंदा की है। हालांकि, यह शीतकालीन सत्र अद्वितीय होगा क्योंकि यह 57 साल बाद नागपुर की बजाय मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बताते चलें कि आमतौर पर राज्य विधानसभा का मानसून और बजट सत्र मुंबई में आयोजित किए जाता है, जबकि शीतकालीन सत्र नागपुर में आयोजित होता है। साल 1961 के बाद पहली बार शीतकालीन सत्र का आयोजन इस बार मुंबई में किया जाएगा। मानसून सत्र का आयोजन 47 वर्षों बाद नागपुर में आयोजित किया गया था।

1953 के नागपुर समझौते के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के निर्माण हुआ था और इसमें नागपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया था। तब यह फैसला किया गया कि विधायिका के सत्रों में से एक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, समझौते ने यह नहीं कहा गया था कि नागपुर में कौन सा सत्र आयोजित किया जाएगा। विधायिका के अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बाद में किया गया था कि यहां शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के अंत में घोषित किया गया कि शीत कालीन सत्र 19 नवंबर को शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान महज 8 कार्य दिवस ही मिलेंगे क्योंकि ईद और गुरुणानाक जयंती को दो सार्वजनिक अवकाश होंगे।

एक अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मांग की थी कि सत्र का समय एक हफ्ते बढ़ाया जाए। हालांकि, सरकार ने मांग को खारिज कर दिया। पारंपरिक रूप से शीतकालीन सत्र दो सप्ताह का होता है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा कि सत्र का विस्तार करने से इंकार करके भाजपा की अगुआई वाली सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से भाग रही है। राज्य में सूखे की स्थिति खतरनाक है और सरकार इससे निपटने के लिए आकस्मिक योजना के साथ तैयार नहीं है।

गुजरात को मिला 'सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार'

नई दिल्ली। गुजरात के किसानों की खेती में अपने विचार और तकनीकी प्रगति के लिए, गुजरात राज्य को नई दिल्ली में 11 वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार-2018 में भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद (आईसीएफए) द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात कृषि मंत्री आरसी फाल्दू को पुरस्कार दे कर सम्मानित किया, गुजरात ने बेहतर खेती प्रथाओं और इसके लिए जागरूकता फैलाने की दिशा में कई नई पहलों को अपनाया है, कृषि महोत्सव, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी, पोस्ट फसल प्रबंधन, डेयरी और पशुपालन जैसे प्रयासों को एक नया रूप दिया था। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक राज्य कपास की फसल, राज्य की सबसे बड़ी खरीफ फसल में गुलाबी-बॉलवार्म खतरे में सफल रहा है. पिछले कुछ वर्षों में, गुजरात ने उपग्रह इमेजरी और जीआईएम मैपिंग के क्षेत्रों में कृषि के लिए ड्रोन सर्वेक्षण में पहल की है।

बांबे हाईकोर्ट का फैसला, शर्त और जुए के दायरे में आती है लाटरी

मुंबई (कासं)। लाटरी को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि यह शर्त और जुआ के दायरे में आती है। यह व्यवस्था देते हुए हाई कोर्ट ने लाटरी टिकटों की बिक्री पर कर लगाने के कर का महाराष्ट्र सरकार के अधिनियम को बरकरार रखा है। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह मंगल मूर्ति मार्केटिंग नाम की कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। कंपनी ने लाटरी पर महाराष्ट्र कर अधिनियम 2006 की वैधता को चुनौती दी थी। यह कंपनी अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड सरकार की लाटरी के सब-डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करती है। कंपनी ने हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राज्य के पश्चिमी हिस्से में लाटरी टिकटों की बिक्री पर कर लगाने या जमा करने से दूर रहने का निर्देश देने की मांग की थी। अधिनियम के तहत लाटरी टिकटों के प्रमोटरों पर कर लगाया गया है। प्रमोटर के लिए कर अधिकारियों को लाटरी योजना से संबंधित स्टेटमेंट देना अनिवार्य किया गया है।

अहम मुद्दों पर बहस से बचना चाहती है सरकार: उन्होंने कहा कि हमने कृषि संकट, सूखा प्रबंधन, मुंबई डेवलपमेंट प्लान और अन्य शहरी मुद्दों के साथ ही मराठा, धनगर और मुसलमानों के आरक्षण की मांग को लंबित करने की सरकार की रणनीति पर बहस करने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा था।

सोयाबीन उत्पादन में इजाफे के आसार

मुंबई (कासं)। सरकार के साथ-साथ किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में इस साल भारत का सोयाबीन उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से 30 प्रतिशत तक बढने के आसार हैं। रकबे में बढ़ोतरी के साथ-साथ कृषि के अनुकूल मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है। अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े बताते हैं कि इस साल भारत का सोयाबीन उत्पादन 1.1 करोड़ टन रहेगा। कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान बताने वाली विश्व की इस प्रमुख एजेंसी ने इससे पहले भारत का कुल सोयाबीन उत्पादन 1.03 करोड़ रहने का अनुमान जताया था। संभवत: मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों समेत सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कृषि की अनुकूल जलवायु परिस्थिति के मद्देनजर इस वैश्विक एजेंसी ने अपने सोयाबीन उत्पादन के अनुमान में संशोधन किया है। महाराष्ट्र के आधे गांव सुखाग्रस्त होने के बावजूद राज्य के कुछ कृषि क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन 2018 के दौरान सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश हुई। भारत में खाद्य तेल और तिलहन क्षेत्र की सेवा में जुटी उद्योग की शीर्ष संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (सी) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि खरीफ सीजन 2017 के दौरान सोयाबीन उत्पादन के संबंध में विशेष वर्ष नजर आया था। हालांकि इस साल सरकार की किसानों के अनुकूल नीतियों के कारण सोयाबीन के अंतर्गत रकबे में इजाफा हुआ है। दरअसल किसानों को उनकी सोयाबीन के लिए अच्छे दाम मिले जिससे उन्हें इस साल तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रोत्साहन मिला। कृषि की अनुकूल जलवायु स्थिति को देखते हुए इस साल उनका अनुमान 1.05-1.1 करोड़ टन सोयाबीन उत्पादन का है। इस बीच 2018-19 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान में भारत का सोयाबीन उत्पादन 1.346 करोड़ टन रहने का पूर्वानुमान जताया गया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.098 करोड़ टन उत्पादन दर्ज किया गया था। इस तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा अनुमानित उत्पादन कुछ हद तक यूएसडीए द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान के सामन ही है।

सम्पादकीय

दूध में मिलावटी का धंधा

देश में बिक रहे करीब 50 फीसदी दूध में मिलावट पाई गई है। जांच के लिए उठाए गए नमूनों में कच्चा और प्रॉसेस्ड, दोनों तरह के दूध शामिल हैं। फसाई (फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सर्वे से यह खुलासा हुआ है। फसाई ने अपने सर्वे के लिए जो नमूने लिए उनमें से 50 प्रतिशत तय मानकों के अनुरूप नहीं थे। गनीमत कहें कि इनमें केवल 10 फीसदी ही स्वास्थ्य के लिए घातक थे, जबकि 39 पर्सेंट की मिलावट पानी आदि की थी और वे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं थे। प्रोसेस्ड दूध के 46.8 फीसदी नमूने तय मानकों के अनुरूप नहीं थे और उनमें 17.3 फीसदी सेहत के लिए खतरनाक थे, जबकि कच्चे दूध के 45.4 प्रतिशत नमूने तय मानकों के अनुरूप नहीं थे और उनमें 4.9 फीसदी हेल्थ पर बुरा असर डालने वाले थे। पिछले महीने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में 68.7 प्रतिशत दूध और दुग्ध उत्पादों में प्रदूषणकारी तत्व मौजूद हैं। दूध में मिलावट की खबरें समय-समय पर आती रहती हैं। लगभग हर वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट गंभीर चिंता प्रकट करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को समुचित निर्देश भी देता है। लेकिन मिलावट पर रोक लगाने की बात किसी भी सरकार के अजेंडा पर नहीं आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ राज्यों ने आईपीसी में बदलाव कर इस मामले में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है, लेकिन इस मामले में किसी को छोटी सजा मिलने की खबर भी आज तक नहीं सुनी गई। कभी-कभार सरकार किसी कंपनी के खिलाफ कुछ करती भी है तो जल्द ही पता चलता है कि वैसे ही करम करने वाली बाकी कंपनियां नियमों में मौजूद छिद्रों का बेहतर इस्तेमाल करके चैन से हैं। अब यह भी कैसी विडंबना है कि दूध जैसी अनिवार्य जरूरत की वस्तु तक हमें शुद्ध नहीं मिल रही है। भारत एक शाकाहार प्रधान देश है और दूध यहां प्रोटीन का सबसे व्यापक स्रोत है। पिछले कुछ सालों में भारत दूध उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल हो गया है।

यहां रोजाना दो लाख गांवों से दूध एकत्रित किया जाता है और डेयरी उद्योग लगातार मजबूत हो रहा है। जरूरत इसे व्यवस्थित रूप देने और ढंग से इस क्षेत्र का रेगुलेशन करने की है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत जांच तंत्र बनाया जाना चाहिए। अभी आलम यह है कि राज्यों ने जरूरी संख्या में फूड इंस्पेक्टरों तक की नियुक्ति नहीं की है। फूड लैब्स की भी भारी कमी है। जहां ये हैं भी वहां इनमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। एक रिपोर्ट आने में छह महीने का वक्त लगता है। ये खामियां दुरुस्त करनी होंगी, लेकिन जिन कंपनियों के नमूनों में मिलावट पाई गई है, उनके नाम तो अभी ही उजागर किए जा सकते हैं।

चने का कमजोर रकबा

मुंबई (कासं)। चने को मजबूत करता कमजोर रकबा रबी सीजन में रकबा कम होने की आशंका के चलते चना हर दिन दमदार हो रहा है। वायदा बाजार में चना करीब एक साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। चालू महीने में चने के दाम 20 फीसदी से बढ़कर 4,700 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गए। देशभर में चने की बुआई करीब 33 फीसदी और दलहन की फसलों की बुआई लगभग 28 फीसदी पिछड़ती दिख रही है। कमजोर बुआई और बेहतरीन मांग की वजह से चने में आगे भी तेजी बनी रहने की संभावना है। वायदा बाजार में करीब एक साल के बाद चना 4,700 रुपये की सीमा को पार कर गया। एनसीडीईएक्स में कारोबार के दौरान चना 4,741 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। हालांकि 4,700 रुपये के नीचे कारोबार बंद हुआ। एक नवंबर को वायदा बाजार में चने की बोली 3,942 रुपये प्रति क्विंटल रही। वायदा की तरह हाजिर बाजार में भी महीने के शुरुआत में चना 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे कारोबार कर रहा था। इस समय हाजिर बाजार में चने के दाम बढ़कर 4,700 रुपये प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गए हैं। हाजिर बाजार में लगभग पूरा साल चना न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिक रहा था। इस बार सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

चने के दामों में अचानक तेजी की मुख्य वजह चालू रबी सीजन में चने के रकबा का कम होना माना जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी फसल बुआई के आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर तक देश में 27.137 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हुई है जो पिछले साल की सामान्य अवधि में देश में चने का रकबा 40.462 लाख हेक्टेयर पहुंच गया था। चना उत्पादक सभी प्रमुख राज्यों में रकबा कम दिखाई दे रहा है। चना उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बुआई संतोषजनक नहीं होने से उत्पादन कम होने की आशंका अभी से जताई जाने लगी है। बढ़ती आशंकाओं के कारण कारोबारी जमकर चने की खरीद रहे हैं।

चना कारोबारी संतोष सिंह कहते हैं कि पिछले कई महीनों से मिलों की तरफ से मांग सुस्त थी जो इस समय रफ्तार पकड़ चुकी है। त्योहारी सीजन के बाद शुरू हो रहे शादी विवाह के सीजन को देखते हुए मिलों में चने की मांग बढ़ी है। घरेलू मांग के साथ विदेशी मांग भी बढ़ने की बात कही जा रही ही है। अप्रैल से सितंबर के बीच चने का निर्यात 172 फीसदी बढ़कर 120,664 टन हुआ है।

सब्जी फसलों के बीज उत्पादन में बरतें ये सावधानियां

विक्रम (स्नातकोत्तर, सब्जी विज्ञान विभाग), संजय (स्नातकोत्तर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग)
नीरज (स्नातकोत्तर,सुत्रकृमि विभाग),चौ. च. सिं. ह. कृषि विश्वविध्यालय

सब्जी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों अच्छे गुणों का बीज किसानों को जरुरत के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार बीजों के दाम अधिक होने के कारण किसान अपने खेत में उनका उपयोग करने में असमर्थ होता है जो कि फसल की अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरुरी है। आईएआरआई करनाल के डॉ. वी.के. पंडिता और डॉ. एस.सी. राणा के अनुसार शुद्ध स्वस्थ बीज का प्रयोग अच्छी फसल के लिए जरुरी है। किसान भाई कुछ विशेष विधियां अपनाकर तकनीकी जानकारी लेकर भी बीज बना सकते हैं।

खेत की तयारी व बीज की बुवाई

❖कीटों से बचाव को मैलाथियान चूर्ण 0.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से दें। बीजों को सुखाना जरूरी है।

❖भंडारण के समय फसलों नमी की मात्रा 7-9 फीसदी हो। समय पर कटाई का महत्व है। असावधानी में बीज गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

❖कोई भी पौधा जो लगाई गई किस्म के अनुरुप नहीं दिखता वह अवांछित है।

❖अच्छे बीज अंकुरण खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत को अच्छी प्रकार से जोतें।

बीज उत्पादन की विधि

बीज से बीज तैयार करना: टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, बेल वर्गीय सब्जियां, मटर में सीधा बीज से बीज तैयार किया जाता है।

कंदसे बीज बनाना: इस विधि से प्याज बीज तैयार करते हैं। इसमें बीज अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है पौध की रोपाई दिसंबर-जनवरी के प्रथम पखवाड़े में करते हैं। शल्क कंद अप्रैल-मई में तैयार हो जाते हैं। खुदाई के बाद चुने हुए स्वस्थ शल्ककंदों को अक्टूबर तक भंडारण में रखते हैं। अक्टूबर-नवंबर में बीज उत्पादन के लिए खेत में लगाते हैं। बीज अप्रैल-मई में निकाला जाता है।

जड़ से बीज बनाना: मूली,शलगम गाजर किस्मों को बीज उत्पादन के लिए दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। मूली शलगम में बिजाई के 45-65 दिन बाद तथा गाजर में 90-100 दिन बाद प्रतिरोपण के लिए जड़ें तैयार होती हैं। पत्तों को काटते समय यह ध्यान रखें कि पादप शिखर को हानि पहुंचे ताकि जड़ प्रतिरोपण के बाद पौधे का फुटाव जल्दी हो सके। छांटी गई जड़ों का प्रतिरोपा 60 सेंटीमीटर मूली, 45 सेंटीमीटर शलगम, 30 सेंमी गाजर की दूरी रखें।

ये बातें ध्यान में जरूर रखें किसान

खेत का चयन: बीज उत्पादन के लिए ऐसी भूमि का चयन हो, जिससे पानी की निकासी सही हो सके। जहां पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपलब्ध हो। खेत खरपतवारों से मुक्त हो। दो साल में उसी किस्म की फसल उगाई हो।

किस्म का चयन: बाजार की मांग के अनुसार ही बीज को प्राथमिकता दें। किस्म अधिक पैदावार, रोग रोधिता, अगेतापन आदि गुण होने चाहिए। छांटी गई किस्म उस क्षेत्र के अनुकूल हो। बीज हमेशा किसी अनुसंधान केंद्र, बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय या सुस्थापित बीज फर्म से लें।

पृथक्करण : दो किस्मों के बीच में एक निर्धारित दूरी जरुर रखें। परागण के आधार पर फसलों के लिए पृथकरण की दूरी अलग-अलग है। स्वपरागित फसल जैसे मटर, सेम, लोबिया के लिए यह दूरी 5 से 20 मीटर रखी जाती है और परपरागित फसलों प्याज, गोभी, खरीरा वर्गीय फसलें के लिए यह दूरी 800 से 1000 मीटर रखी जाती है।

मधुमक्खियों का प्रयोग: पर-परागित फसलों में मधुमक्खियों अन्य कीटों द्वारा समुचित मात्रा में परागण होने से इन फसलों में बीज उपज बीज गुणवत्ता बढ़ जाती है।

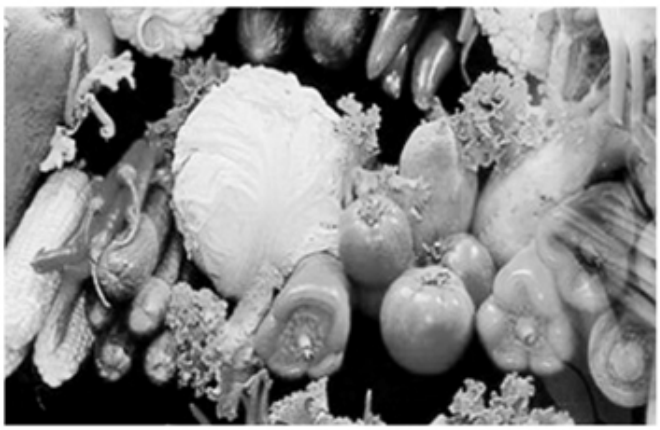

सरसों की फसल के मुख्य कीट एवं उनकी रोकथाम

सुनीता यादव एवं सुगन्ध पाल सिंह
तिलहन अनुभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125 004

तिलहन की फसलों में सरसों (तोरिया, राया और सरसों) का भारत वर्ष में विशेष स्थान है तथा यह हरियाणा प्रदेश में रबी की मुख्य फसल है। सरसों में अनेक प्रकार के कीट समय-समय पर आक्रमण करते हैं लेकिन 4-5 कीट ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन कीटों की सही पहचान कर उचित रोकथाम की जाएं। इस लेख में सरसों के कीटों के लक्षण व उनकी रोकथाम के उपाय दिये गए है

बालों वाली सुण्डी (कातरा)

इस कीट की तितली भूरे रंग की होती है, जो पत्तियों की निचली सतह पर समूह में हल्के पीले रंग के अण्डे देती है। पूर्ण विकसित सुण्डी का आकार 3-5 सैं. मी. लम्बा होता है। इसका सारा शरीर बालों से ढका होता है तथा शरीर के अगले व पिछले भाग के बाल काले होते है। इस सुण्डी का प्रकोप अक्तूबर से दिसम्बर तक, तोरिया की फसल में अधिक होता है तथा कभी-कभी राया व सरसों की फसलें भी इसके आक्रमण की चपेट में आ जाती है । नवजात सुण्डियां आरम्भ में, 8-10 दिन तक, समूह में पत्तियों को खाकर छलनी कर देती है तथा बाद में अलग-अलग होकर पौधों की मुलायम पत्तियों, शाखाओं, तनों व फलियों की छाल आदि को खाती रहती हैं जिससे पैदावार में भारी नुकसान होता है।

नियन्त्रण

❖फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी में रहने वाले प्युपे को बाहर आने पर पक्षी उन्हें खा जाएं अथवा धूप से नष्ट हो जाएं ।

❖ऐसी पत्तियां जिन पर अण्डे समूह में होते हैं, को तोड़कर मिट्टी में दबाकर अण्डों को नष्ट कर दें।

❖इसी तरह छोटी सुण्डियों सहित पत्तियों को तोड़कर मिट्टी में दबाकर अथवा केरोसीन या रसायन युक्त पानी में डूबोकर सुण्डियों को नष्ट कर दें।

❖इस कीड़े का अधिक प्रकोप हो जाने पर 250 मि.ली. मोनोक्रोटोफास या 500 मि.मी. एण्डोसल्फान (थायोडान) 35 ई.सी. या 500 मि.ली. क्विनलफास (इकालक्स) 25 ई.सी.या 200 मि.ली. डाईक्लोरवास (नूवान) 76 ई.सी. को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें ।

चितकबरा कीड़ा या धौलिया कीड़ा

यह कीड़ा काले रंग का होता है, जिस पर लाल, पीले, व नारंगी के धब्बे होते है। इस कीड़े के शिशु हल्के पीले व लाल रंग के होते हैं। दोनों प्रौढ़ व शिशु इन फसलों को दो बार नुकसान पहुंचाते हैं, पहली बार फसल उगने के तुरन्त बाद सितम्बर से अक्तूबर तक तथा दूसरी बार फसल की कटाई के समय फरवरी-मार्च में। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियों का रंग किनारों से सफेद हो जाता है, अत: इस कीड़े को धौलिया भी कहते हैं। फसल पकने के समय भी कीड़े के प्रौढ़ व शिशु फलियों से रस चूसकर दानों में तेल की मात्रा को कम कर देते हैं जिससे दानों के वजन में भी कमी आ जाती है ।

नियन्त्रण

❖फसल की बिजाई तब करें जब दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए ।

❖फसल में सिंचाई कर देने से प्रौढ़, शिशु एवम् अण्डे नष्ट हो जाते हैं ।

❖बीज को 5 ग्राम ईमिडाक्लोपरिड 70 डब्लयू. एस. प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें।

❖फसल की शुरू की अवस्था में 200 मि.ली. मैलाथियान 50 ई. सी. को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

❖मार्च-अप्रैल में यदि जरूरत पड़े तो 400 मि.ली. मैलाथियान 50 ई.सी. को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़कें।

आरा मक्खी

इस कीड़े की मक्खी का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है । सुण्डियों का रंग गहरा हरा होता है जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की तीन कतारें होती है। पूर्ण विकसित सुण्डियों की लम्बाई 1.5-2.0 सैं.मी. तक होती है । इस कीड़े की सुण्डियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट-काट कर खा जाती है। इस कीड़े का अधिक प्रकोप अक्तूबर-नवम्बर में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुण्डियां तने की छाल तक भी खा जाती है।

नियन्त्रण

❖गर्मियों में खेत की गहरी जोताई करें ।

❖सुण्डियों को पकड़ कर नष्ट कर दें ।

❖फसल की सिंचाई करने से कीड़े की सुण्डियां डूब कर मर जाती है।

❖फसल में इस कीड़े का प्रकोप होने पर मैलाथियान 50 ई.सी. की 200 मि.ली. मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें ।

चेपा (माहू/अल)

यह कीड़ी हल्के हरे-पीले रंग का 1.0 से 1.5 मि.ली. लम्बा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाये जाते है। इसका प्रकोप दिसम्बर मास के अंतिम सप्ताह में (जब फसल पर फूल बनने शुरू होते हैं) होता है व मार्च तक बना रहता है। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुँचाते है। लगातार आक्रमण रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणामस्वरूप पौधों की भोजन बनाने की ताकत कम हो जाती है जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीट ग्रस्त पौधे की वृद्धि रूक जाती है जिसके कारण कभी-कभी तो फलियां भी नहीं लगती और यदि लगती हैं तो उनमें दाने पिचके एवम् छोटे हो जाती हैं।

नियन्त्रण

❖समय पर बिजाई की गई फसल (10-25 अक्तूबर तक) पर इस कीट का प्रकोप कम होता है।

❖राया जाति की किस्मों पर चेपे का प्रकोप कम होता है।

❖दिसम्बर के अन्तिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जहां इस कीट के समूह दिखाई दें उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें।

❖जब खेत में कीटों का आक्रमण 20 प्रतिशत पौधों पर हो जाये या औसतन 13-14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो निम्नलिखित कीटनाशियों में से किसी एक का प्रयोग करें।

आक्सीडिमेटान मिथाईल (मैटासिस्टाक्स) 25 ई.सी. या डाइमैथोएट (रोगोर) 30 ई.सी. की 250, 350 व 400 मि.ली. मात्रा को क्रमश: 250, 350 व 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कीट ग्रस्त फसलों पर पहला, दूसरा तथा तीसरा छिड़काव 15 दिन के अन्तराल पर करें। अगर कीड़ों का आक्रमण कम हो तो छिडकावों की संख्या कम की जा सकती है। छिड़काव सॉंय के समय करें, जब फसल पर मधुमक्खियां कम होती है। मोटर चालित पम्प में कीटनाशक दवाई की मात्रा ऊपरलिखित होगी लेकिन पानी की मात्रा 20 से 40 लीटर प्रति एकड़ हो जायेगी । साग के लिए ऊगाई गई फसल पर 250 से 500 मि.ली. मैलाथियान 50 ई.सी. को 250 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें । यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 7 से 10 दिन के अन्तराल पर करें।

सुरंग बनाने वाला कीड़ा

इस कीड़े की मक्खियां भूरे रंग तथा आकार में 1.5-2.0 मि.ली. होती है। सुण्डियों का रंग पीला व लम्बाई 1.0-1.5 मि.ली. होती है। जनवरी से मार्च के महीनों में सुण्डियां पत्तियों के अन्दर टेढ़ी-मेढ़ी सुरंगे बनाकर हरे पदार्थ को खा जाती है जिससे पत्तियों की भोजन बनाने की क्रिया कम हो जाती है व फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है।

नियन्त्रण

❖कीटग्रस्त पत्तिया को तोड़कर नष्ट करें या मिट्टी में दबा दे ताकि और मक्खियां न बन सकें ।

❖इस कीड़े का आक्रमण चेपा के साथ ही होता है इसलिए चेपे के नियन्त्रण के लिए अपनाए जाने वाले कीटनाशियों के प्रयोग से इस कीट का आक्रमण भी रूक जाता है।

अधिक एमएसपी के कारण पंजाब, हरियाणा में बढ़ी अनाज की तस्करी

चंडीगढ़ (विसं)। पंजाब और हरियाणा में इस सीजन में अनाज की तस्करी बढ़ गई है। इसके पीछे न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और इन राज्यों में अनाज की सरकारी खरीद बेहतर होना प्रमुख कारण हैं। देश में अनाज का बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाले पंजाब और हरियाणा की अथॉरिटीज ने अन्य राज्यों से अनाज की आवक को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इन राज्यों में खरीफ के मार्केटिंग सीजन के लिए सरकारी खरीद चल रही है।

राज्यों के बॉर्डर से सटे जिलों से गेहूं और धान हरियाणा और पंजाब में आता रहा है। इन दोनों राज्यों में देश का सबसे बड़ा सरकारी खरीद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और भुगतान की प्रक्रिया बेहतर होने से अनाज की काला बाजारी में मार्जिन बढ़ा है। पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फूड एंड सिविल सप्लाई), के ए पी सिन्हा ने बताया, ऐसी गतिविधियों से राज्य में स्टोरेज की क्षमता पर असर पड़ता है और सरकार को वित्तीय नुकसान होता है। उनका कहना था कि इससे पता चलता है कि अन्य राज्यों में एमएसपी लागू करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। पंजाब पिछले कुछ वर्षों के लिए अनाज की खरीद की लगभग 31,000 करोड़ रुपये की बकाया रकम को चुकाने में मुश्किल का सामना कर रहा है। पिछले महीने पंजाब में बिहार से आया धान पकड़ा गया था जिसे एक ट्रेडिंग कंपनी एमएसपी पर बेच रही थी। सिन्हा ने कहा कि इस समस्या की जानकारी केंद्र को दी गई है। उन्होंने बताया, राज्य पर बोझ पड़ने के अलावा इससे यह भी पता चलता है कि बिहार में किसानों को फसल के लिए बहुत कम दाम मिल रहा है क्योंकि गड़बड़ी करने वाले ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और अन्य खर्च चुकाने के बाद भी मुनाफा कमा रहे हैं। पंजाब में किसानों को एमएसपी मिल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में किसानों को अभी भी यह लाभ उपलब्ध नहीं है। हरियाणा में फूड एंड सिविल सप्लाई के डायरेक्टर संजीव वर्मा ने बताया, बॉर्डर के निकट जिलों में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को बाहर से आने वाले अनाज की निगरानी के लिए कहा गया है। हरियाणा ने तस्करी से निपटने के लिए इस वर्ष बाजरे की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य किया है।

गन्ने की नई किस्म लगाएं, सूखे और बाढ़ में भी नहीं बर्बाद होगी फसल

लखनऊ (कासं)। इस समय प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसान गन्ना की बुवाई कर रहे हैं, ऐसे में किसान भारतीय गन्ना शोध संस्थान से विकसित उन्नत प्रजातियों का चयन कर सूखे और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसान गन्ना उगाते हैं। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां के किसानों को बाढ़-सूखा जैसी समस्याओं से परेशान होना पड़ता है। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना शोध संस्थान (आईआईएसआर) के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार साह ने बताया कि संस्थान में गन्ने की उन्नत किस्मों पर शोध हो रहा था, जिस पर सूखे और बाढ़ का असर कम हो। गन्ने की इस प्रजाति सीओएलके 94184 और ओपीके 05191 पर रिसर्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में 40-45 जिलों में किसान गन्ने की खेती करते हैं, 35 लाख से ज्यादा किसान सीधे तौर पर गन्ने की खेती से जुड़े हैं।

यूपी में 168 गन्ना समितियां हैं। साथ ही 119 गन्ना मिल और 2700 करोड़ से ज्यादा लोग गन्ने से जुड़ा व्यवसाय करते हैं। इन किस्मों की खेती में कम पानी की जरूरत होती है, खरीफ और रबी दोनों सीजन में बुवाई कर सकते हैं। मार्च में लगाए गए गन्ने की सिंचाई पांच से छह बार करनी होती है। उन्नत की बुवाई कर किसान पहले साल प्रति हेक्टेयर 75 से 80 टन की पैदावार ले सकते हैं। वहीं अगले दो से तीन वर्षों तक इससे 70 टन की पैदावार ली जा सकती है। इन किस्मों की खेती में कम पानी की जरूरत होती है, खरीफ और रबी दोनों सीजन में बुवाई कर सकते हैं। मार्च में लगाए गए गन्ने की सिंचाई पांच से छह बार करनी होती है। डॉ. अजय कुमार साह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गन्ना शोध संस्थान नए रिसर्च में ऐसी किस्में विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कम पानी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर पैदावार हो सके।

महिन्द्रा ट्रैक्टर की बिक्री अक्टूबर में 17 प्रतिशत बढ़कर 47,376 इकाई

नई दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने अक्टूबर में 47,376 ट्रैक्टर बेचे जो बिक्री पिछले साल इसी महीने की 40,562 इकाई की बिक्री से 17 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि घरेलू बाजार में, ट्रैक्टर की बिक्री अक्टूबर 2017 के 39,516 इकाइयों के मुकाबले इस बार बिक्री 46,312 इकाई की हुई, जो 17 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है।

जैविक उत्पादों की ओर रूख कर रही रसायन कंपनियां

नई दिल्ली (विसं)। रासायनिक दवाओं एवं कीटनाशकों के उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर बढ़ते दुष्प्रभाव के लिए देश में जैविक खेती की मांग बढ़ रही है और कंपनियां इसमें अपने लिए लाभ के अवसर तलाशने लगी हैं। कृषि रसायन क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों ने कई ऐसे नये उत्पाद पेश करने की पहल की है जो उनके दावे के मुताबिक जैविक खेती में मदद करने वाले हैं।

देश में घटते भूजल स्तर तथा अत्यधिक रासायनिक दवाओं एवं कीटनाशकों के उपयोग के कारण खेत के बंजर होने एवं मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के होने की घटनाओं के बीच सरकार भी राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में लगी है। जैविक खेती और जैविक खाद्य उत्पादों पर दिए जा रहे जोर के बीच कृषि रसायन कंपनियां जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। जैविक खेती से निश्चित रूप से खेती की लागत कम होती है और उपज अच्छी होने पर किसानों का लाभ बढ़ सकता है।

सेब की फसल बरबाद

मुंबई (कासं)। फसल क्षति के कारण आपूर्ति में बाधा पड़ने की वजह से पिछले एक सप्ताह के दौरान थोक और खुदरा बाजारों में सेब के दामों में उछाल आई है। हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम एक सप्ताह पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत तक बढ़कर फिलहाल 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में सेब 22 प्रतिशत तक महंगा होकर फिलहाल 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा है जबकि एक सप्ताह पहले दाम 45 रुपये प्रति किलोग्राम थे। मौसम से पहले सर्दियों के हिमपात के कारण मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में फसल बरबाद होने की वजह से सेब के दामों में अचानक तेजी आई है। आजकल जम्मू-कश्मीर में सेब की तुड़ाई चल रही है। इसलिए क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण पकी हुई फसल बरबाद हो गई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की सूचना मिली थी लेकिन पकी फसल की तुड़ाई पूरी होने के कारण वहां फसल की क्षति उतनी गंभीर नहीं रही। पूरे भारत में सेब उत्पादकों और मध्यस्थों का प्रतिनिधित्व करने वाली शिमला स्थित व्यापारिक संस्था ऐपल ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रवींद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब के ज्यादातर पौधे निष्क्रिय चरण में हैं क्योंकि फल की पहले ही तुड़ाई की जा चुकी हैं।

गन्ना किसान चाहते हैं प्रति क्विंटल 400 रुपये दाम

लखनऊ (कासं)। देश के प्रमुख चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश में पेराई कार्य के धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने के साथ ही राज्य के किसानों ने 2018-19 सीजन में गन्ने के दाम 25 प्रतिशत बढ़ाकर प्रति क्विंटल करीब 400 रुपये करने की मांग की है। यह मांग ऐसे समय में की जा रही कि जब निजी मिलों ने पिछले साल 2017-18 सीजन में निर्धारित किए गए गन्ने (सामान्य किस्म) के मौजूदा दाम प्रति क्विंटल 315 रुपये पर ही भुगतान करने में अपनी असमर्थता की बात दोहराई है। डीजल, उर्वरक और अन्य कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) संशोधित कर 400 रुपये करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने कार्यक्रम पर तो जोर दे रही हैं लेकिन इसके बावजूद हाल के वर्षों में गन्ने के दामों में मामूली-सा ही इजाफा हुआ है।

टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली (विसं)। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने टमाटर, प्याज और आलू फसलों के दामों में उतार-चढ़ाव के बिना पूरे वर्ष इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशंस ग्रीन' स्कीम की गाइडलाइंस को स्वीकृति दे दी है। इस स्कीम पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम से किसानों को इन फसलों से मिलने वाली आमदनी में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए उत्पादन क्षेत्रों और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 'टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के दामों में अधिक वृद्धि से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इन फसलों के दामों में स्थिरता लाने और पूरे वर्ष इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। स्कीम के तहत सरकार ने इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय पेश किए हैं। दामों में स्थिरता लाने के उपायों को लागू करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी होगी। इस स्कीम के तहत सभी क्षेत्रों में चुनिंदा प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 50 पर्सेंट अनुदान दिया जाएगा। मिनिस्ट्री उत्पादन से स्टोरेज तक फसलों को फसलों को पहुंचाने के खर्च पर 50 पर्सेंट सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। मिनिस्ट्री स्टोरेज की सुविधाओं को भी बढ़ाएगी। वैल्यू चेन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्षमता बढ़ाने, कटाई के बाद प्रोसेसिंग की सुविधाओं, एग्री लॉजिस्टिक्स, बिक्री के लिए ई-प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करेगी। टमाटर के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात, आलू के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात और प्याज के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में उत्पादन क्षेत्र होंगे।

Hindchem Corporation

AMINO+HUMIC SHINY BALLS · FERROUS SULPHATE19%
MAGNESIUM SULPHATE 9.6% · FERROUS EDTA12%
E.D.T.A. ACID · CAMPHOR · SODIUM BICARBONATE
EDTA DISODIUM · CITRIC ACID MONOHYDRATE
MANGANESE SULPHATE 30.5%
SULPHUR 90% -80WDG · BORON 20%
BRONOPOL 25% · PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

स्मार्ट स्प्रैयर से रूकने लगी कीटनाशकों की बर्बादी

नई दिल्ली (विसं)। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं, सही स्प्रेयर के प्रयोग न होने से कीटनाशकों की बर्बादी हो जाती है, ऐसे में स्मार्ट स्प्रेयर किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर आधारित एक स्वचालित स्प्रेयर विकसित किया है इसके उपयोग से कीटनाशकों के उपयोग में आसानी से कटौती की जा सकती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि संकेतों पर आधारित इस स्प्रैयर को किसी भी ट्रैक्टर पर आसानी से लगाकर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। जब ट्रैक्टर को बगान में घुमाया जाता है तो इसको वहां घुमाते वक्त यह स्प्रैयर जैसे ही पौधों के करीब पहुंचता है तो यह तुरंत ही सक्रिय हो जाता है और खाली जगह पर पहुंचने पर यह बंद हो जाता है। इस स्प्रैयर का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के राहुरी स्थित रिसर्च फार्म में अनाज के बगान में किया जाता है। इस अध्ययन से जुड़े शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान

संस्थान के वैज्ञानिक ब्रजेश नारे ने बताया, कीटनाशकों के छिड़काव की यह स्मार्ट तकनीक दोनों परंपरागत छिड़काव पद्धतियों को प्रतिस्थापित करके किसानों के स्वास्थ्य और संसाधनों को बचाने में मददगार हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा सप्रैयर तकनीक का यह है कि इसके सहारे छिड़काव करने पर कीटनाशकों के उपयोग में 26 प्रतिशत तक बचत दर्ज की गई है। इसके साथ ही फलों में संक्रमण रोकने में भी इसकी दक्षता का स्तर 95.64 प्रतिशत तक प्रभावी पाया गया है।

ये है स्प्रैयर की खास बातः इस कीटनाशक स्प्रैयर की खास बात यह है कि इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, सोलीनॉइड वॉल्व, एक-तरफा वॉल्व, स्थाई विस्थापन पंप, प्रेशर गेज, और रिलीफ वॉल्व लगाया गया है. 12 वॉल्ट बैटरी से चलने वाले इस स्प्रैयर में 200 लीटर का स्टोरेज टैंक लगा है।

हस्तचलित तकनीक से ज्यादा बेहतर स्प्रैयर तकनीकः बागानों में किसान आमतौर पर हस्तचालित छिड़काव या मशीनी छिड़काव करते हैं। इन दोनों तरीकों में काफी खामियां हैं। हस्तचालित पद्धति में छिड़काव करने वाले व्यक्ति को स्प्रेयर अपने हाथ में लेना पड़ता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। मशीनी छिड़काव प्रणाली में कीटनाशक का निरंतर छिड़काव होते रहने से काफी मात्रा में रसायन बरबाद हो जाता है। दूसरी ओर सेंसर आधारित यह नया स्प्रेयर सिर्फ चयनित पौधों पर ही कीटनाशक का छिड़काव करने में सक्षम हैं।

कृषि विवि के वीसी के बयान पर विवाद

भजन करने से होती है अच्छी पैदावार

नागपुर (विसं)। महाराष्ट्र में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर विलास भाले के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम में भाले ने बयान दिया था कि पवित्र भजन करके फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद से ही विदर्भ में इसपर सवाल उठे हैं। कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के उद्घाटन भाषण में भाले ने भारतीय कला और संस्कृति की महानता के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने कहा, शास्त्रीय संगीत मवेशियों में दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और भजन से फसलों को बढ़ने में मदद मिलती है।

विदर्भ के कई किसान संगठनों ने भाले के इस बयान की आलोचना की है और उनके बयान पर सवाल उठाया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनके खिलाफ एक पत्र जारी किया है और उनसे सवाल किए हैं। इसके बाद भाले ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया।

भाले ने कहा कि उनके बयान को गलत व्याख्या की गई और उन्होंने कभी नहीं कहा कि पवित्र भजन फसलों को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके बजाय उन्होंने कहा कि भजन करने से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है, उनका यह बयान शास्त्रीय संगीत के संबंध में था।

किसानों को बताए सरसों के उत्पादन में उन्नत खेती के गुर

अंता। कस्बे में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से केलवाड़ा क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में सरसों उत्पादन तकनीकों पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. डीके सिंह ने बताया कि किसानों को सरसों उत्पादन की जानकारियां दी गई। किसानों को सरसों की उन्नत खेती की जानकारी के साथ बीज की किस्म, बीज उपचार, खेत की तैयारी, खाद व उर्वरक प्रबंधन तथा कीट बीमारियों की रोकथाम की जानकारी दी।

पराली जलाने से घटती है जमीन की उपजाऊ शक्ति

दातारपुर (विसं)। खेतों में पराली जलाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। जमीन से कीट, केंचुए और जीवाणु मर रहे हैं। वायुमंडल भी दूषित हो रहा है, जिससे लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। अगर समय रहते नहीं चेते तो भविष्य में जमीनों के बंजर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। पराली न जलाने को लेकर विचारों में विशेषज्ञों ने कहा कि इसकी वजह लचर कानून व्यवस्था है। पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सख्ती न होने से किसान बेखौफ होकर खेत में पराली जला देते हैं। हालांकि जिले में ऐसे किसानों की तादाद ज्यादा नहीं है। मौसम पर प्रभाव की अगर बात की जाए तो धुएं की वजह से कार्बन डाई आक्साइड भी निकलती है। जिससे सेहत को नुकसान होता है। किसानों में आम धारणा है कि पराली जलाने से खेत की जुताई कम करनी पड़ती है। ऐसे में कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों को जागरूक करने में भी जुटा है। किसानों को गोष्ठी एवं मेलों के माध्यम से पराली जलाने के नुकसान बताए जा रहे हैं। इनके तहत किसानों को पराली जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के बारे में समझाया जाता है। किसानों को यह भी बताया जाता है कि फसल के अवशेषों को खेत में ही मिला देने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन अभी भी कुछ किसान पराली जलाने के नुकसानों से बेखबर हैं। ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए सरकारों, प्रशासन, एनजीटी को किसानों को पराली न जलाने और इसके सदुपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए।

मार्च तक होगी 100 से ज्यादा खनिज ब्लॉकों की नीलामी!

नई दिल्ली। सरकार 50 खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी से 1.81 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के बाद अब अगले छह महीने में 102 और खानों की नीलामी करने पर विचार कर रही है। खान मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सरकार अब तक 50 खानों की नीलामी कर चुकी है। जिसमें 23 चूना पत्थर, 17 लौह अयस्क, चार सोना, मैंगनीज और ग्रेफाइट के दो-दो ब्लॉक और बॉक्साइट एवं हीरे के एक-एक ब्लॉक शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार का नया प्लान, होगी शराब की होम डिलिवरी

नागपुर (कासं)। एक ओर जहां देश में कुछ राज्य सरकारें शराबबंदी लागू कर चुकी हैं, महाराष्ट्र सरकार इससे एकदम उलटे रास्ते पर है। राज्य सरकार ऐसी नीति लागू करने की योजना बना रही है जिसके तहत लोगों के घरों पर शराब की डिलिवरी की जा सकेगी। एक्साइज राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनखुले ने बताया कि इससे शराब इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने बताया, ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करना है। नैशनल और इंटरनैशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की तरह एक प्लैटफॉर्म पर शराब को लोगों के घर तक शराब पहुंचाई जाएगी, जैसे राशन और सब्जियां पहुंचती हैं। नैशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों को मुताबिक 2015 में 4.64 लाख सड़क हादसों में से 1.5 फीसदी शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुए थे जिससे 6,295 लोग घायल हो गए थे। इन हादसों में 2,988 लोगों की मौत हो गई थी।

उम्र वेरिफिकेशन के लिए आधारः शराब खरीदने के लिए उम्र वेरिफाई करने के लिए वेबसाइट्स को ग्राहकों के आधार नंबर समेत वह सारी जानकारी लेनी होगी जिससे उम्र वेरिफाई की जा सके। मंत्री ने बताया कि शराब की बोतलों पर जियो-टैग लगा होगा जिससे उन्हें खरीद-फरोख्त पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया, बोतलों के ढक्कन पर टैग लगा होगा। विक्रेता से ग्राहक तक बोतल को ट्रैक किया जाएगा। इससे मिलावटी शराब और तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए हाई कोर्ट के वकील श्रीरंग भंडारकर ने कहा कि इससे व्यस्त लोगों का समय बचेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हादसों में कमी आएगी और डिलिवरी की व्यवस्था से लोगों को रोजगार मिलेगा।

बढ़ेगी शराब की लतः हालांकि, शराबबंदी की मांग कर रहीं ऐक्टिविस्ट पोरमिता गोस्वामी इस फैसले के विरोध में हैं। उन्होंने इसे असंवैधानिक फैसला बताया और कहा है कि इसके दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे।

शराब की नहीं, किसानों को मदद की होम डिलिवरी करोः उद्धव ठाकरे

मुंबई (कासं)। शराब की होम डिलिवरी करने के मुद्दे पर चौतरफा आलोचना के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हों, लेकिन सरकार में शामिल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि सरकार को शराब की होम डिलिवरी करने के बजाए सूखाग्रस्त किसानों को मदद की होम डिलिवरी करना चाहिए। उद्धव ने अपने बयान में कहा है कि शराब की होम डिलिवरी महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। राज्य के आबकारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की थी कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलिवरी की अनुमति देने जा रही है, लेकिन उनकी इस घोषणा की जब सब तरफ से आलोचना होने लगी, तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि इस तरह के आवेदन सरकार के पास आए हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आबकारी मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी यह घोषणा करनी पड़ी थी कि शराब की होम डिलिवरी की अनुमति की कोई योजना नहीं है। इसी मुद्दे को उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, लोग बारिश की कमी के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। शराब की ऑनलाइन बिक्री राज्य की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, लेकिन हर दिन सरकार द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है जो राज्य को शर्मिंदा करता है।

यू एस एग्रोकेम प्रा.लि.
Wholesale Supplier
सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार

व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है

प्लाट नं. बी-81, 82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)
E-mail : suresh@hindchem.com, Contact : 9004744077

केले की उन्नत खेती के निर्देश

1ओम प्रकाश, 2डॉ. बालाजी विक्रम, 3प्रवीण चोयल,3सुमन चौधरी व संदीप कुमार
1,2शुआट्स, इलाहबाद, उत्तरप्रदेश

दुनियाभर में केला एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत में लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है जिससे 180 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के कुल केला क्षेत्र का 70 फीसदी अकेले जलगांव जिले में है। देशभर के कुल केला उत्पादन का लगभग 24 फीसदी भाग जलगांव जिले से प्राप्त होता है। केले को गरीबों का फल कहा जाता है। केले का पोषक मान अधिक होने के कारण केरल राज्य एवं युगांडा जैसे देशों में केला प्रमुख खाद्य फल है। केले के उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण केले की खेती का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केले की खेती में यह देखा गया है कि किसान अक्सर अज्ञानतावस थोड़ी-थोड़ी कमियों के कारण केले की खेती का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

केला से निर्मित उत्पाद: केला चिप्स, केला फिग, केला आटा, केला पापड, केला हलवा, केला जूस, केला पल्प, केला फल केनिंग, केला टाफी, केला मदिरा, केला शेम्पेन इत्यादि सामग्रियां तैयार की जाती हैं।

जलवायु: केला उत्पादन के लिये उष्ण तथा आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है जहां पर तापक्रम 20-35 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है वहां पर केले की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। वार्षिक वर्षा 150-200 से.मी. समान रूप से वितरित होना चाहिये। शीत एवं शुष्क जलवायु में भी इसका उत्पादन होता है। परंतु पाला एवं गर्म हवाओं (लू) आदि से काफी क्षति होती है।

भूमि: केले की खेती के लिए बलुई से मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। जिसका पी. एच मान 6.5-7.5 एवं उचित जल निकास का होना आवश्यक हैं। केले की खेती अधिक अम्लीय एवं क्षारीय भूमि में नहीं की जा सकती है। भूमि का जलस्तर 7-8 फीट नीचे होना चाहिये।

केले की व्यवसायिक प्रजातिया:

-ड्वार्फ केवेन्डिस (भुसावली, बसराई, मारिसस, काबुली, सिन्दुरानी, सिंगापुरी जहाजी, मोरिस) : यह प्रजाति म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एवं कर्नाटक की जलवायु के लिये बहुत उपयुक्त पायी गयी है। इस प्रजाति से चयन कर गनदेवी सिलेक्शन (हनुमान) अथवा पाडर्से नाम की जातियां विकसित की गई हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 20-25 कि. ग्रा. प्रति पौधा है। इस प्रजाति का पौधा बोना किस्म का 1.5-1.8 मीटर ऊंचा होता है फल बडे, मटमैले पीले या हरेपन लिये हुये पीला होता है। तना मौटा हरा पीलापन लिये हुए होता है। पत्तियां चौड़ी एवं पीली होती हैं औसतन 9-10 हेण्ड प्रति बंच (गुच्छा) होता है। औसत फिंगर की लम्बाई 20 सें.मी. एवं मोटाई 10 से.मी. होती है।

(2) रोबस्टा (एएए) इसे बाम्बेग्रीन, हरीछाल, बोजीहाजी आदि नामों से अलग-अलग प्रांतों में उगाया जाता है। इस प्रजाति को पश्चिमी दीप समूह से लगाया गया है। पौधों की ऊंचाई 3-4 मीटर, तना मध्यम मोटाई हरे रंग का होता है। प्रति पौधे में 10-19 हेण्ड्स में फर्टाइल पुष्प होते हैं जिनमें हरे रंग की फिंगर विकसित होती है। बंच का वजन औसतन 25-30 किलो ग्राम होता है। फल अधिक मीठे एवं आकर्षक होते हैं। फल पकने पर चमकीले पीले रंग का हो जाता है। यह प्रजाति सिंगाटोक (लीफस्पॉट) बीमारी से काफी प्रभावित होती है। फलों की भंडारण क्षमता कम होती है।

रस्थली (सिल्क एएबी): इस प्रजाति को मालभोग अमृत पानी सोनकेला रसवाले आदि नामों से विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है पौधे की ऊंचाई 2.5-3.0 मीटर होती है पुष्पन 12-14 माह के बाद ही प्रारंभ होता है। फल (फिंगर) चार कोण वाले हरे, पीले रगं के मोटे होते हैं। छिलके पतला होते है जो पकने के बाद सुनहरे पीले रगं के हो जाते हैं। केले का बंच 15 से 20 किलोग्राम का होता है। फल अधिक स्वादिष्ट सुगन्ध पके सेब जैसी कुछ मिठास लिए हुए होता है। केले का छिलका कागज की तरह पतला होता है इस प्रजाति की भण्डारण क्षमता कम होती है।

पूवन (एबी) : इसे चीनी चम्पा, लाल वेल्ची और कदली कोडन के नाम से जाना जाता है इसका पौधा बेलनकार मध्यम ऊंचाई का 2.25-2.75 मीटर होता है। रोपण के 9-10 महीने में पुष्पण प्रांरभ हो जाता है। इसमें 10-12 हेण्ड्स रहते हैं। प्रत्येक हेंड में 14-16 फिंगर आती है, फल छोटे बेलनाकार एवं उभरी चोंच वाले होते हैं। फल का गूदा हाथी के दांत के समान सफेद एवं ठोस होता है। इसे अधिक समय तक भण्डारित किया जा सकता है। फल पकने के बाद भी टूटकर बंच से अलग नहीं होते।

करपूरावल्ली (एबीबी) : इसे बोन्था, बेन्सा एवं केशकाल आदि नामों से जाना जाता है। यह किस्म किचन गार्डन में लगाने लिए उपयुक्त पाई गई है। इसका पौधा 10-12 फिट लम्बा होता है। तना काफी मजबूत होता है। फल गुच्छे में लगते है। फल पर तीन रिंज (उभार) होते हैं। एक पौधे में 5-6 पंजे बनते हैं जिसमें 60-70 फल होते हैं। इनका वजन 18-20 किलोग्राम होता है। फल मोटे नुकीले और हरे पीले रंग के होते हैं। यह चिप्स एवं पाउडर बनाने के लिये सबसे उपयुक्त प्रजाति है।

नेन्द्रन (प्लान्टेन एएबी) : इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई है। इसे सब्जी केला या रजेली भी कहते हैं। इसका उपयोग चिप्स बनाने में सर्वाधिक होता है। इसका पौधा बेलनाकार मध्यम मोटा तथा 3 मीटर ऊंचाई वाला होता है। गुच्छे में 4-6 हेण्ड्स और प्रत्येक हेण्ड में 8-14 फिंगर होती हैं। फल 20 से.मी. लम्बा, छाल मोटी तथा थोड़ा मुड़ा एवं त्रिकोणी होता है। जब फल कच्चा होता है तो इसमें पीलापन रहता है। परंतु पकने पर छिलका कड़क हो जाता है। इसका मुख्य उपयोग चिप्स एवं पाउडर बनाने के लिये किया जाता है।

केले की उन्नत संकर प्रजातियां:

एच-1 (अग्निस्वार पिसांग लिलिन) : यह लीफस्पॉट फ्यूजेरियम बीमारी निरोधक कम अवधि वाली उपर्युक्त किस्म है। यह बरोइंग सूत्र कृमि के लिए अवरोधक है। इस संकर प्रजाति का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है और इसमें लगने वाले बंच का वजन अमूमन 14 से 16 किलोग्राम का होता है। फल लम्बे, पकने पर सुनहरे या पीले रगं के हो जाते हैं। पकने पर इसमें हल्का खट्टा तथा मीठी खट्टी महक आती है। यह किस्म जड़ी फसल के लिये उपयुक्त है। तीन वर्ष के फसल चक्र में चार फसलें ली जा सकती हैं।

रोपण सामग्री (फसल उत्पादन तकनीक):

केला रोपण हेतु तलवारनुमा आकार के अतंभूस्तरीय जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं, जिनको बीज के उपयोग में लाया जाता है। तीन माह पुराना सकर्स जिसका वजन 700 ग्राम से 1 कि.ग्राम तक हो, रोपण के लिए उपर्युक्त होते हैं।

वर्तमान में केले के टिश्यू कल्चर पौधे व्यावसायिक रूप से उत्पादकों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं। क्योंकि इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीमारी रहित उत्तम गुणवत्ता वाले अधिक उत्पादक मातृ वृक्षों से ऊतक निकालकर प्रवर्धित किया जाता है। टिशु कल्चर पौधे ट्रू-टू दि टाईप जिनोटाइप चयनित ऊतक को विट्रोंकल्चर पद्धति से वर्धित किया गया है। टिशु पौधों का स्वभाव दैहिक होता है और इसकी फसल एक साथ परिपक्व होती है। इसकी जड़ी (रेटून) से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।

भूमि की तैयारी एवं रोपण पद्धति: खेत की जुताई कर मिट्टी को भूरी-भूरी बना लेना चाहिये जिससे भूमि का जल निकास उचित रहें तथा कार्बनिक खाद ह्यूमस के रूप में प्रचुर मात्रा में हो इसके लिये हरी खाद की फसल ले।

पौध अंन्तराल: कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखते हैं तथा पौधा रोपण के लिये 45×45×45 सें. मी. आकार के गड्ढे खोदे प्रत्येक गड्डे में 12-15 किग्रा. अच्छी पकी हुई गोबर या कम्पोस्ट खाद रोपण के पूर्व साथ ही प्रत्येक गड्डे में 5 ग्राम थिमेट दवा मिट्टी में मिला दें।

बीज उपचार: प्रकंदों को उपचार के पूर्व साफ करें तथा जड़ों को प्रथक कर दें। 1 प्रतिशत बोर्डो मिक्चर तैयार कर प्रकंदों को उपचारित करें इसके बाद 3-4 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर प्रकंदों को 5 मिनट तक उपचार करें।

प्रकंदों के रोपण का समय: केला के प्रकंदों को अत्यधिक ठण्ड व वर्षा को छोड़कर पूरे वर्ष भर रोपण किया जा सकता हैं। प्राय: अप्रैल से जून: इस फसल की रोपाई मई जून महीने में की जाती है। जिसमें केले के साथ, मूंग, भिण्डी, टमाटर, मिर्च, बैंगन इत्यादि फसले ले सकते हैं। (ग्रीष्म) की फसल से अधिक उत्पादन मिलता है।

खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं देने की विधि: केले की फसल अपने पूरे जीवन चक्र में रोपण 5-7 माह के अन्दर प्रति पौधा नत्रजन 200 ग्राम, स्फुर 40-50 ग्राम और पोटाश 250-300 ग्राम, कम्पोस्ट खाद 5 कि.ग्रा. एवं कपास या महुए की खली प्रति पौधा के हिसाब से दें। कम्पोस्ट खाद एवं फास्फोरस की पूर्ण मात्रा पौधा लगाते समय नत्रजन एवं पोटाश एक माह के अन्तराल से सात से आठ माह के अन्दर सात से आठ बार में दें।

केले की फसल में शस्य क्रियाए: केले की फसल में पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। क्योंकि केले की जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं। इसलिये पौधों को सहारा देने के लिए मिट्टी चढ़ाना जरूरी है। कभी-कभी कंद बाहर आ जाते हैं। जिससे पौधे की वृद्धि रूक जाती है। इसलिए मिट्टी चढ़ाना जरूरी है।

मल्चिंग: जमीन से जल वाष्पीकरण तथा खरपतवार द्वारा ह्रास होता है तथा भूमि से पोषक तत्व भी खरपतवारों द्वारा लिए जाते हैं। भूमि जल के वाष्पीकरण एवं खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्लास्टिक सीट पौधे की जड़ों के चारों ओर लगाने से उपरोक्त क्षति से बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त गन्ने के छिलके, सूखी घास, सूखी पत्तियां एवं गुड़ाई करने से जल ह्रास कम हो जाता है। प्लास्टिक की काली पॉलीथिन की मल्चिंग करने पर उत्पादकता में वृध्दि होती है।

अतंभूस्तरी (सकर्स) निकालना: जब तक केले के पौधे में पुष्प गुच्छ न निकल पाएं तब तक सकर्स को नियमित रूप से काटते रहे। पुष्पण जब पूर्ण हो जावे तो एक सकर्स को रखा जाए तथा शेष को काटते रहे। यह ध्यान रखे कि एक वर्ष की अवधि तक एक पौधे के साथ एक सर्कस को ही बढ़ने दिया जाए यह जड़ी (रेटून) की फसल के रूप में उत्पादन देगा, बंच के निचले स्थान में जो नर मादा भाग है इस काटकर उसमें बोर्डोपेस्ट लगा दिया जाए।

सहारा देना: जिन किस्मों में बंच का वजन काफी हो जाता है तथा स्युडोस्टेंम के टूटने की संभावना रहती है। इसे बल्ली का सहारा देना चाहिए, केले के पत्ते से उसके डंठल को ढ़क दिया जाए।

पौधों को काटना: केला बंच पुष्पण से 110 से 130 दिनों में काटने योग्य हो जाते हैं। बंच काटने के पश्चात पौधों को धीरे-धीरे काटें, क्योंकि इस क्रिया से मातृ प्रकंद के पोषक तत्व जड़ी वाले पौधे को उपलब्ध होने लगते हैं। फसलस्वरूप उत्पादन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है।

जल प्रबंधन: केले की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते बड़े चौड़े होते हैं। एक पौधे के पत्तों का कुल क्षेत्रफल 50-60 वर्गमीटर होता है। इसलिए बड़े पैमाने पर पानी की वाष्पीकरण उत्सर्जन होने से केले को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। केले के पूर्ण वर्धित झाड़ों को प्रतिदिन 12-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने पर 60 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

फसल संरक्षण:

पनामा विल्ट या उकठा रोग: यह बीमारी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के द्वारा फैलती है पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती है केले का पूरा तना फट जाता है। प्रारंभ में पत्तियां किनारों से पीली पड़ती हैं प्रभावित पत्तियां डण्ठल से मुड़ जाती है। प्रभावित पीली पत्तियां तने के चारों ओर स्कर्ट की तरह लटकती रहती है। आधार पर (निचले भाग) तने का फटना बीमारी का प्रमुख लक्षण है। बैस्कूलर टिश्यू जड़ों और प्रकंद में पीले, लाल एवं भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधा कमजोर हो जाता है जिसके कारण पुष्पन फलन नहीं होता है। इस बीमारी की फफूंद जमीन में अनुकूल तापक्रम, नमी एवं पी. एच. की स्थिति में लम्बी अवधि तक रहता है।

नियंत्रण:

-गन्ना एवं सूरजमुखी के फसल चक्र को अपनाने से बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है।

-सकर्स को लगाने के पूर्व 0.2 प्रतिशत बाविस्टीन के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर लगाना चाहिए।

-ट्राइकोडर्मा बिरिडी जैविक फफूंद नाशक का उपयोग करना चाहिए।

-जिलेटिन केप्सूल में 50 ग्राम बाविस्टीन भरके केप्सूल अप्लीकेटर के सहारे कंद मे 45 डिग्री कोण पर रखने से बीमारी पर अच्छा नियंत्रण देखा गया है। (शेष पेज 7 पर)

पेज 6 का शेष...

केले की उन्नत खेती के निर्देश...

लीफ स्पाट (सिंगाटोका): यह बीमारी स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसी फफूंद के कारण होती है। इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्योंकि टिशू हरे से भूरे रंग के हो जाते हैं। धीरे-धीरे पौधे सूखने लगते है। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे धब्बे दिखायी देते हैं। फिर यह पीले या हरी पीली धारियों में बदल जाते हैं। जो पत्तियों को दोनों सतहों पर दिखाई देते हैं। अंत में यह धारियां भूरी एवं काली हो जाती हैं। धब्बों के बीच का भाग सूख जाता है।

नियंत्रण:

-प्रभावित सूखी पत्तियों को काटकर जला देना चाहिए। फफूंद नाशक दवायें जैसे डाइथेन एम-45, 1250 ग्राम/हेक्टेयर या बाविस्टीन 500 ग्राम/ हेक्टेयर या प्रोपीकनोजोल 0.1 फीसदी का छिड़काव टिपॉल के साथ अक्टूबर माह से 3-4 छिड़काव 2-3 सप्ताह के अंतराल से करने से बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

एन्थ्रेक्नोज: यह बीमारी कोलेट्रोट्राईकम मुसे नामक फंगूद के कारण फैलती है। यह बीमारी केले के पौधे में बढ़वार के समय लगती है। इस बीमारी के लक्षण पौधो की पत्तियों, फूलों एवं फल के छिलके पर छोटे काले गोल धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इस बीमारी का प्रकोप जून से सितम्बर तक अधिक होता है क्योंकि इस समय तापक्रम ज्यादा रहता है।

नियत्रण:

-प्रोक्लोराक्स 0.15 प्रतिशत या कार्बेन्डिज्म 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।

-केले को 3/4 परिपक्वता पर काटना चाहिये।

शीर्षगुच्छा रोग: (बंचीटाप): पत्तियों की भीतरी मिडरिब की द्वीतियक नसों के साथ अनियमित गहरी (मोर्सकोड) धारियां शुरू के लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं। ये असामान्य लक्षण गहरे रंग की रेखाओं में एक इंच या ज्यादा लम्बे अनियमित किनारों के साथ होते हैं। पौधों का ऊपरी सिरा एक गुच्छे का रूप ले लेता है। पत्तियां छोटी व संकरी हो जाती हैं। किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। डंठल छोटे व पौधे बौने रह जाते हैं और फल नहीं लगते हैं। इस बीमारी के विषाणु का वाहक पेन्टोलोनिया नाइग्रोनरवोसा नामक माहू है।

नियत्रण:

-रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।

-रोग वाहक कीट नियंत्रण के लिये मेटामिस्टॉक्स 1.25 मि.ली. या डेमेक्रान 0.5 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

-रोग रहित सकर्स का चुनाव करें।

केले का धारी विषाणु रोग: इस बीमारी के कारण प्रारंभ में पौधों को पत्तियों पर छोटे पीले धब्बे जो बाद में सुनहरी पीली धारियों में बदल जाते हैं। क्लोरोटिक धारियां पत्तियों के लेमिना पर काला रूप लिये नेक्रोटिक हो जाती हैं। घेर का बहार न निकलना, बहुत छोटी घेर निकलना एवं फलों में बीज का विकास प्रभावित पौधों के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग का विषाणु मिलीबग एवं प्लेनोकोकस स्पिट्री के द्वारा फैलाया जाता है।

नियंत्रण:

-प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये तथा मिलीबग के नियंत्रण के लिये कार्बोफ्यूरान की डेढ़ किलो ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में डालें।

कीट एवम् उनका नियंत्रण:

केला प्रकंद छेदक (राइजोम बीबिल): यह कीट केले के प्रकंद में छेद करता है। इसको इल्ली प्रकंद के अन्दर छेद करती है। परन्तु वह बाहर से नहीं दिखायी देती है। कभी-कभी केले के स्यूडोस्टेम में भी छेद कर देता है। इन छिद्रों में सड़न पैदा हो जाती है।

नियंत्रण:

-प्रकंदों को लगाने से पहले 0.5 फीसदी मोनोक्रोटोफास के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें। अत्याधिक प्रकोप होने पर 0.03 फीसदी फास्फोमिडान के घोल का छिड़काव करें।

तना भेदक: तना भेदक कीट का मादा वयस्क पत्तियों के डंठलों में अण्डे देती है जिससे इल्ली निकलकर पत्तियों एवं तने को खाती है। प्रारंभ में पौधे के तने से रस निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर कीट की लार्वा द्वारा किए गए छिद्र से गंदा पदार्थ पत्तियों के डंठल पर बूंद-बूंद टपकता है जिससे तने के अन्दर निकल रहे पुष्प प्रोमोडिया शुष्क हो जाता है। इसका प्रकोप वर्ष भर होता है।

नियंत्रण:

-मोनोक्रोटोफास की 150 मि.ली. मात्रा 350 मि.लीटर पानी में घोलकर तने में इंजेक्ट करें।

-घेर को काटने के बाद पौधों को जमीन से काटकर कीट नाशक दवा कार्बोरिल 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से अंडे व कीट नष्ट हो जाते हैं।

माहू: यह कीट केले की पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है तथा बंचीटाप वायरस को फैलाने का प्रमुख वाहक है। इस माहू का रंग भूरा होता है। जो पत्तियों के निचले भाग या पौधे के शीर्ष भाग से रस चूसती है।

नियत्रण:

-फारफोमिडान 0.03 फीसदी या मोनोक्रोटोफास 0.04 फीसदी के घोल का छिड़काव करें।

थ्रिप्स: तीन प्रकार की थ्रिप्स केला फल (फिंगर) को नुकसान पहुंचाती है। थ्रिप्स प्रभावित फल भूरा बदरंग, काला तथा छोटे-छोटे आकार के आ जाते हैं। यदपि फल के गूदे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता पर इनका बाजार भाव ठीक नहीं मिलता।

नियंत्रण:

-मोनोक्रोटोफास 0.05 फीसदी का घोल बनाकर छिड़काव करें तथा मोटे कोरे कपड़े से बंच को ढंकने से भी कीट का प्रकोप कम होता है।

पत्ती खाने वाली इल्ली: इस कीट की इल्ली नये छोटे पौधों की बिना खुली पत्तियों को खाती है। पत्तियों में नये छेद बना देती है।

नियंत्रण:

-थायोडान 35 ई. सी. का छिड़काव (1.5 मि. ली. प्रति लीटर पानी) पत्तियों पर करने से प्रभावी नियंत्रण देखा गया है।

उपरोक्त बातों पर ध्यान देने से किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता हैं।

एक रुपए पहुंची टमाटर की कीमत

मुंबई (कासं)। देश की प्रमुख टमाटर मंडियों में टमाटर की कीमत एक रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। मतलब टमाटर सड़कों पर फेंकने का समय आ गया है और ऐसा पहली बार नहीं होगा। सरकार के तमाम दावे और आश्वासन फिर फेल होते दिख रहे हैं। देश की सबसे बड़ी टमाटर मंडी नासिक के पिपलगांव में टमाटर का न्यूनतम भाव 200 रुपए प्रति कुंतल तक पहुंच गया है। जबकि 23 और 24 सितंबर को तो भाव 150 रुपए कुंतल हो गया था। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) के आंकड़ों अनुसार महाराष्ट्र में नासिक जिले की बेंचमार्क पिंपलगांव मंडी में अच्छी गुणवत्ता वाला टमाटर 1.50-2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बिका है। टमाटर की कीमत इस एक बार फिर कौड़ियों के भाव तक पहुंच गयी है। किसानों को मजबूरन टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी टमाटर मंडियों में कीमत पिछले एक महीने से लगातार गिर रही है। गिरते-गिरते कीमत अब तो एक से दो रुपए प्रति किलो तक पहुंच गयी है। ऐसे में मंडी तक टमाटर ले जाने, ले आने का खर्च तक नहीं निकल पा रहा। देश के कई हिस्सों से टमाटर सड़कों पर फेंकने की खबरें आने लगी हैं। टमाटर की आवक बहुत ज्यादा है। ऐसे में कीमत तेजी से गिर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा टमाटर जा नहीं रहा, ऐसे में कीमत कितनी नीचे जा सकती है ये कहना मुश्किल है। उत्पादकों का नुकसान और बढ़ सकता है। सरकार अगर आयात पर कुछ करे तो शायद स्थिति सुधर जाये। महाराष्ट्र में एक रुपए किलो तक पहुंची टमाटर की कीमत सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में 548 करोड़ रुपए का टमाटर भारत ने निर्यात किया था कि जो 2017-18 में गिरकर 107 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के टमाटर एक्सपोर्ट को गहरा झटका लगा है। पाकिस्तान को 2016-17 में 368 करोड़ का टमाटर एक्सपोर्ट किया था जो कि घट कर पिछले साल 34 लाख ही रह गया। देश की अन्य बड़ी मॉडियों में भी हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी टमाटर मंडी आंध्र प्रदेश के चीत्तूर जिले की मदनपल्ली में भी यही हाल है।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

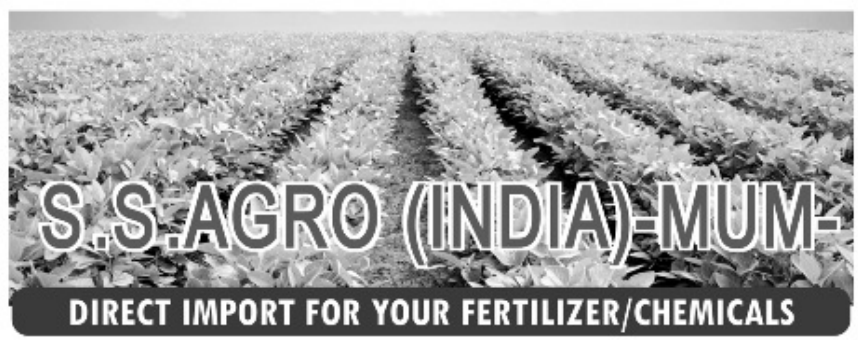

- ZINK EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC

ORGANIC CHEMICALS

CONTACT NO. 022-6710-3722

पिंक बॉलवर्म के हमले और बढ़ती लागत से
संकट में महाराष्ट्र के कपास किसान

सुरेश शर्मा

नागपुर/छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र और उसके सीमावर्ती मध्य प्रदेश के कपास किसान अब हार मानने लगे हैं। लगातार होते नुकसान के कारण कपास से उन्हें सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लग रहा। इस साल भी पिंक बॉलवर्म के हमले के बाद अब फसल को बचाने के लिए चार से पांच बार दवा का छिड़काव करना पड़ रहा। मजदूरी भी बढ़ गयी है। लेकिन कपास की कीमत वैसी नहीं बढ़ी जैसे महंगाई बढ़ रही। ऐसे में कपास किसानों का अब कपास से धीरे-धीरे मोह भंग हो रहा। पिंक बॉलवॅर्म ने पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की कपास फसल को नुकसान पहुंचाया है और तीसरी बार भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। इस बार केंद्र सरकार ने इस कीड़े की वजह से हुए नुकसान के लिए महाराष्ट्र कपास किसानों के दावों को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। यह पहली बार नहीं हुआ कि पिंक बॉलवर्म कपास किसानों के लिए आफत बनकर आया है। लेकिन इससे जूझते-जूझते अब किसानों का दम जवाब देने लगा है। रही सही कसर कम बारिश ने पूरी कर दी है। महाराष्ट्र

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 15 जून से पहले बोई गयी कपास पर पिंक बॉलवर्म का असर ज्यादा है। इसके लिए ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल को भी कारण बताया जा रहा है। कम बारिश के कारण के इसका असर बढ़ा है। लेकिन क्या इसके लिए बस किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा जिले के उन क्षेत्रों में भी कपास की खेती खूब होती है जो नागपुर से सटे हुए। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनात्रा कहते हैं कि मराठवाड़ा और खांदेश क्षेत्रों में बारिश कम हुई। बादल भी छाये रहे। इस कारण पिंक बॉलवर्म का हमला ज्यादा हुआ। पिछले साल भी महाराष्ट्र के कपास किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस कारण इस सीजन में किसानों ने सोयाबीन की ज्यादा बुआई की है। महाराष्ट्र में कपास का रकबा तीन फीसदी घटा है जबकि सोयाबीन का चार फीसदी बढ़ा है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कपास की बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में लगभग चार फीसदी कम हुआ है। इसके लिए इस खेती में बढ़ते घाटे को कारण बताया जा रहा है। सीएआई के अनुसार, महाराष्ट्र में कपास वर्ष 2016-17 (अक्टूबर से सितंबर) में कपास की बुआई 37 लाख हेक्टेयर में की गई थी जबकि उत्पादन 89 लाख गांठ था और 2017-18 में रकबा बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर हो गया जबकि फसल उत्पादन घटकर 82 लाख गांठ रह गया और 2018-19 में शुरुआती संकेतों से पता चला है कि रकबा घटकर 38 लाख हेक्टेयर रह जाएगा जबकि फसल उत्पादन 75 से 80 लाख गांठ के साथ काफी कम रह सकता है।

मुंबई में पानी की किल्लत से अब मंत्री भी परेशान

मुंबई (कासं)। अब तक तो यही माना जा रहा था कि उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे राज्य के इलाकों में लोग सूखे से जैसे स्थिति की वजह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। केवल आमजन ही नहीं, महाराष्ट्र के दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों को मुंबई शहर में पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। मंत्रालय के सामने बने बंगलों की पानी की समस्या के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मुंबई महानगरपालिका से बाकायदा शिकायत की है। मंत्रालय के सामने गुजरने वाले मैडम कामा रोड में पानी कम होने की शिकायत पिछले 10 दिनों से बनी हुई है। इस इलाकों में मंत्रियों और नेताओं के बंगलों के अलावा मंत्रालय के सामने 18 मंजिला नई प्रशासनिक बिल्डिंग भी है। इस बिल्डिंग में राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त समेत 35 महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। साथ लगे बंगले हैं, जहां दो कैबिनेट मंत्रियों चंद्रकांत दादा पाटील और बबनराव लोणीकर के अलावा एक दर्जन राज्यमंत्रियों को अलॉट किए गए बंगले हैं।

आपूर्ति के निर्देश: इस संदर्भ में बीएमसी से बार-बार संपर्क करने के बाद भी समस्या हल न होने के बाद इस समस्या को तत्काल हल करने का पत्र लोकनिर्माण विभाग ने बीएमसी को लिखा है।कम दबाव से पानी आपूर्ति होने से रोजमर्रा का काम काफी प्रभावित हो रहा है। पत्र में इस समस्या का समाधान निकालने तक 8-10 टैंकर पानी आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।

बारिश कम होने से गिरा जलस्तर : इस साल अपेक्षाकृत कम बारिश होने से पूरे मुंबई के सामने यह चुनौती आ गई है। झीलों में जलस्तर 89 प्रतिशत के पास है जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत कम है। इसी वजह से बीएमसी ने पानी आपूर्ति को लेकर नया प्लान बनाया है।

इन मंत्रियों के बंगलों में जल समस्या

चंद्रकांतदादा पाटील, बबनराव लोणीकर, दीपक केसरकर, विद्या ठाकुर, रवींद्र वायकर, रवींद्र चव्हाण, सदाशिव खोत, मदन येरावर, दिलीप कांबले, विजय देशमुख, संजय राठौड़, दादाजी भुसे, विजय शिवतारे, अंबरीश राजे आत्राम। विपक्ष के नेता बालासाहेब विखे पाटील और धनंजय मुंडे।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर

1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर

1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

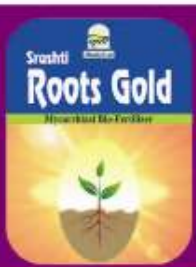

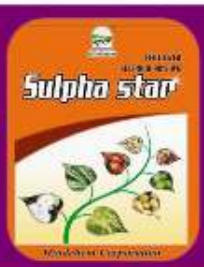

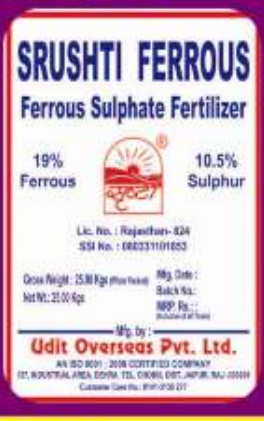

FERTILIZER

- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425